04

अध्याय

कीमतें और मुद्रास्फीति

वाणिज्य अधीक्षक को मांग या मांग के अभाव में, भू अथवा जल मार्ग से लाए गए, भू अथवा जल उत्पादित विविध प्रकार के उत्पादों की कीमत में वृद्धि या कमी को सुनिश्चित करना होगा और इसके साथ ही उन्हें उचित वितरण, केन्द्रीकरण, खरीद और बिक्री को भी सुनिश्चित करना होगा।

कौटिल्य-अर्थशास्त्र, अध्याय XVI, 'वाणिज्य अधीक्षक', पुस्तक II, 'सरकारी अधीक्षकों के कर्तव्य।'

वित्त वर्ष 2019 के दौरान हेडलाईन (सीपीआई-सी) मुद्रास्फीति, खाद्य मुद्रास्फीति के कम रहने के कारण निरन्तर, कमी की ओर अग्रसर थी। वित्त वर्ष 2019 के प्रथम सात महीनों में से छः महीनों में मुख्य मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत से ऊपर थी, जो नवम्बर के बाद सामान्य होना शुरू हुई। सेवाओं और वस्तुओं में भिन्न-भिन्न रुझान रहे। ग्रामीण मुद्रास्फीति सामान्य थी परन्तु शहरी मुद्रास्फीति में पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 में बढ़ोतरी हुई। वर्ष के दौरान राज्यों में भी मुद्रास्फीति में गिरावट हुई।

परिचय

4.1 अर्थव्यवस्था में पिछले पांच वर्षों में उच्च और अस्थिर मुद्रास्फीति में स्थिर और निम्न दर की मुद्रास्फीति की ओर गमन हुआ है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक-संयुक्त (सीपीआई-सी) पर आधारित हेडलाईन मुद्रास्फीति में पिछले पांच वर्षों में नियमित रूप से गिरावट हो रही है। हेडलाईन सीपीआई मुद्रास्फीति 2018-19 में घटकर 3.4 प्रतिशत रह गई। जो 2017-18 में 3.6 प्रतिशत, 2016-17 में 4.5 प्रतिशत, 2015-16 में 4.9 प्रतिशत और 2014-15 में 5.9 प्रतिशत थी। यह अप्रैल 2018 के 4.6 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल 2019 में 2.9 प्रतिशत थी। उपभोक्ता खाद्य कीमत सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति में वित्त वर्ष 2018-19 में 0.1 प्रतिशत की गिरावट हुई।

4.2 थोक कीमत सूचकांक (डब्ल्यू पी आई) पर आधारित मुद्रास्फीति 2016-17 में 1.7 प्रतिशत, 2015-16 में (-) 3.7 प्रतिशत और 2014-15 की 1.2 प्रतिशत की तुलना में 2017-18 में 3.0 प्रतिशत के स्तर पर सामान्य रही। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति 4.3 प्रतिशत थी। कीमत सूचियों की मुख्य श्रृंखला पर आधारित, पिछले सात वर्षों की मुद्रास्फीति तालिका 1 में दी गई है और अप्रैल 2014 से थोक कीमत सूचकांक और उपभोक्ता कीमत सूचकांक में उतार-चढ़ाव चित्र-1 में दिए गए हैं।

तालिका 1: विभिन्न सूचकांकों के अनुसार सामान्य मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
डब्ल्यूपीआई	6.9	5.2	1.2	-3.7	1.7	3.0	4.3 (पी)
सीपीआई (संयुक्त)	9.9	9.4	5.9	4.9	4.5	3.6	3.4
सीपीआई (आईडब्ल्यू)	10.4	9.7	6.3	5.6	4.1	3.1	5.4
सीपीआई (एएल)	10.0	11.6	6.6	4.4	4.2	2.2	2.1
सीपीआई (आरएल)	10.2	11.5	6.9	4.6	4.2	2.3	2.2

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, थोक कीमत सूचकांक के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उपभोक्ता कीमत सूचकांक के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (संविदाओं) और सीपीआई (आईडब्ल्यू), सीपीआई (एएल) तथा सीपीआई (आरएल) के लिए श्रम ब्यूरो।
टिप्पणी: पुरानी श्रृंखला 2010=100 पर आधारित 2012-13 और 2014-15 के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक (समिश्र) मुद्रास्फीति। पी: अनंतिम
सी का अर्थ है संयुक्त, आईडब्ल्यू का अर्थ है औद्योगिक कामगार, एएल का अर्थ है कृषि श्रमिक, और आरएल का अर्थ है ग्रामीण श्रमिक।

चित्र 1: थोक कीमत सूचकांक और उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)

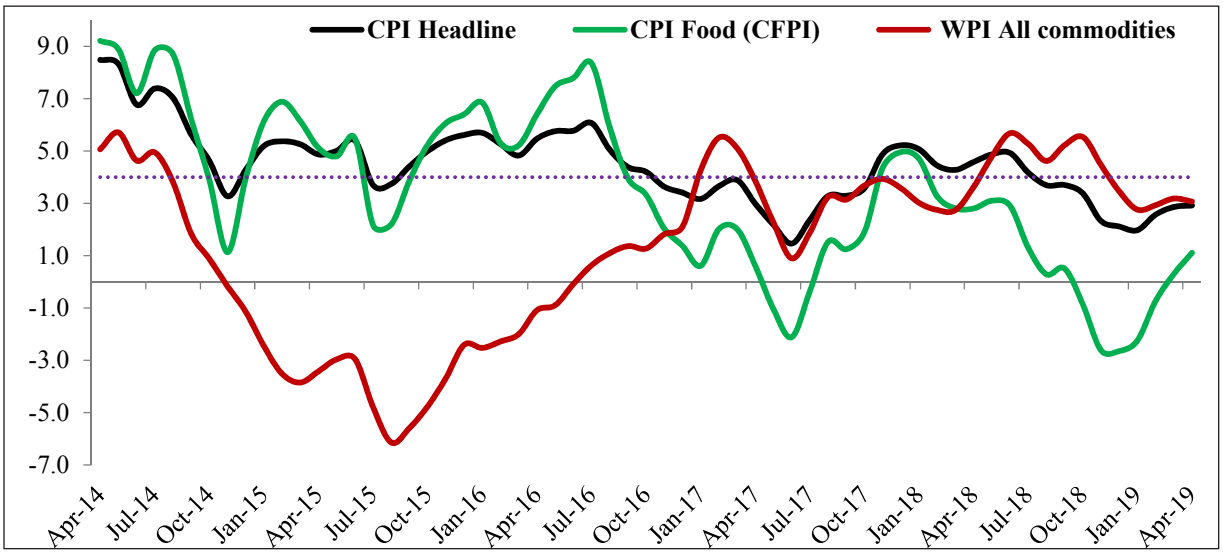

स्रोत: सीएसओ एंव आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीपीआईआईटी आंकड़ों से परिकलित किया गया है।

मुद्रास्फीति में वर्तमान प्रवृत्तियां

4.3 औसत सीपीआई-सी हेडलाईन मुद्रास्फीति में 2018-19 में 3.4 प्रतिशत तक गिरावट हुई, जो सीपीआई की नई श्रृंखला शुरू हाने से लेकर न्यूनतम औसत है। हेडलाईन सीपीआई-सी मुद्रास्फीति लगातार दो वर्षो से 4 प्रतिशत से कम रही है। वित्त वर्ष 2018-19 में मुद्रास्फीति में गिरावट मुख्यत: कम खाद्य मुद्रास्फीति के कारण रही, जो -2.6 प्रतिशत से 3.1 प्रतिशत के बीच रही। वर्ष 2018-19 के दौरान (चित्र-1) के लगातार आठ महीनों के दौरान सामान्य मुद्रास्फीति दर को 4 प्रतिशत से कम रखा गया। अप्रैल 2019 में सीपीआई-सी मुद्रास्फीति मार्च, 2019 के समान 2.9 प्रतिशत थी, जो अप्रैल 2018 में 4.6 प्रतिशत थी।

4.4 देश में खाद्य मुद्रास्फीति अत्यधिक अनुकूल रही है। वैश्विक खाद्य मुद्रास्फीति भी सामान्य रही है। उपभोक्ता खाद्य कीमत सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति में 2016-17 की 4.2 प्रतिशत से 2017-18 में 1.8 प्रतिशत तक गिरावट हुई, जो 2015-16 में 4.9 प्रतिशत और 2014-15

में 6.4 प्रतिशत थी। औसत खाद्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2018-19 में 0.1 प्रतिशत तक कम हुई। खाद्य मुद्रास्फीति मार्च 2019 के 0.3 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल 2019 में 1.1 प्रतिशत थी और अप्रैल 2018 में यह 2.8 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 2018-19 की दूसरी छमाही में खाद्य वस्तुओं में अपस्फीति का मुख्य कारण सब्जियों, फलों, दालों और दाल से बने उत्पादों, चीनी और मीठे खाद्य उत्पादों और अण्डों की कीमतों में गिरावट है, जो समग्र सीपीआई-सी का 13.1 प्रतिशत बैठता है, समग्र सीपीआई-सी में सब्जियों का हिस्सा 6.04 प्रतिशत बैठता है। इसमें 2018-19 में 5.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। दालें और उत्पाद जिनका हिस्सा 2.4 प्रतिशत है, उनमें भी वित्तीय वर्ष 2018-19 में 8.3 प्रतिशत मुद्राअवस्फीति दर्ज की गई। दाल कीमतों में उतार चढ़ाव कम रहे हैं। सबसे दालों में मूंग दाल की कीमतों में कम उतार-चढ़ाव देखा गया (चित्र-2)।

4.5 विगत दो वित्तीय वर्षों में थोक कीमत सूचकांक पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट आई है। यह 2018-19 में 0.6 से अधिक थी। 2018-19 के दौरान डब्ल्यूपीआई खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट मुख्यत: दालों, सब्जियों, फलों और चीनी की कीमतों में गिरावट के कारण हुई है, जो समग्र डब्ल्यूपीआई बॉस्केट का 5.2 प्रतिशत बैठता है। डब्ल्यूपीआई खाद्य मुद्रास्फीति अप्रैल 2018 में 0.8 प्रतिशत और मार्च 2019 में 3.9 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल 2019 में 4.9 प्रतिशत थी।

4.6 'कोर इन्फ्लेशन' मुद्रास्फीति के उस घटक के अनुसार चलती है जिसके लंबे समय तक चलने

तालिका 2: उपभोक्ता कीमत सूचकांक के चुनिंदा समूहों में मुद्रास्फीति-आधार 2012 (प्रतिशत में)

विवरण	भारांश	2017-18	2018-19	मार्च-18	मार्च-19	अप्रैल-19 (पी)
सभी समूह	**100**	**3.6**	**3.4**	**4.6**	**2.9**	**2.9**
सीएफपीआई*	***39.1***	***1.8***	***0.1***	***2.8***	***0.3***	***1.1***
खाद्य एवं पेय पदार्थ	***45.9***	***2.2***	***0.7***	***3.0***	***0.7***	***1.4***
अनाज एवं उत्पाद	9.7	3.5	2.1	2.6	1.2	1.2
मांस एवं मच्छी	3.6	3.2	4.0	3.6	6.5	7.5
अण्डे	0.4	3.6	2.3	6.2	1.4	1.9
दूध एवं उत्पाद	6.6	4.1	1.8	3.2	0.8	0.4
तेल और वसा	3.6	1.6	2.1	2.2	1.1	0.7
फल	2.9	4.6	2.3	9.7	-5.9	-4.9
सब्जियां	6.0	5.8	-5.2	7.5	-1.5	2.9
दालें एवं उत्पाद	2.4	-21.0	-8.3	-12.3	-2.2	-0.9
चीनी और मीठे उत्पाद	1.4	6.1	-7.0	-4.1	-6.1	-4.0
ईंधन एवं प्रकाश	**6.8**	**6.2**	**5.7**	**5.2**	**2.3**	**2.6**
सीपीआई खाद्य एवं ईंधन समूह को छोड़कर (प्रमुख)	***47.3***	***4.6***	***5.8***	***6.1***	***5.1***	***4.5***

स्रोत: सीएसओ पी: अनंतिम *उपभोक्ता खाद्य कीमत सूचकांक

तालिका 3: थोक कीमत सूचकांक के चुनिंदा समूह में मुद्रास्फीति-आधार 2011-2012 (प्रतिशत में)

विवरण	भारांश	2017-18	2018-19	मार्च-18	मार्च-19 (पी)	अप्रैल-19 (पी)
सभी वस्तुएं	**100**	**3.0**	**4.3**	**3.6**	**3.2**	**3.1**
खाद्य सूचकांक	**24.4**	**1.9**	**0.6**	**0.8**	**3.9**	**4.9**
खाद्य वस्तुएं	***15.3***	***2.1***	***0.4***	***0.9***	***5.7***	***7.4***
अनाज	2.8	0.3	5.5	0.2	8.9	8.4
दालें	0.6	-27.1	-9.4	-22.5	10.6	14.3
सब्जियां	1.9	18.8	-8.2	-0.4	28.1	40.6
फल	1.6	5.0	-1.7	19.4	-7.6	-6.9
दूध	4.4	4.0	2.4	2.5	1.8	1.5
अण्डे, मांस और मच्छी	2.4	2.0	1.7	-2.0	5.9	6.9
खाद्य उत्पाद	***9.1***	***1.6***	***1.0***	***0.6***	***0.5***	***0.6***
खाद्य तेल	2.6	2.2	7.5	11.2	-2.4	-5.0
चीनी	1.1	3.4	-10.7	-15.6	-2.2	5.1
ईंधन एवं विद्युत	**13.2**	**8.1**	**11.6**	**8.0**	**5.4**	**3.8**
खाद्य-भिन्न विनिर्मित उत्पाद (प्रमुख)	***55.1***	***3.0***	***4.2***	***3.8***	***2.5***	***1.9***

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीपीआईआईटी पी: अनंतिम

चित्र 2: दालों की थोक कीमत का गिरता हुआ परिवर्तनशील गुणांक (प्रतिशत)

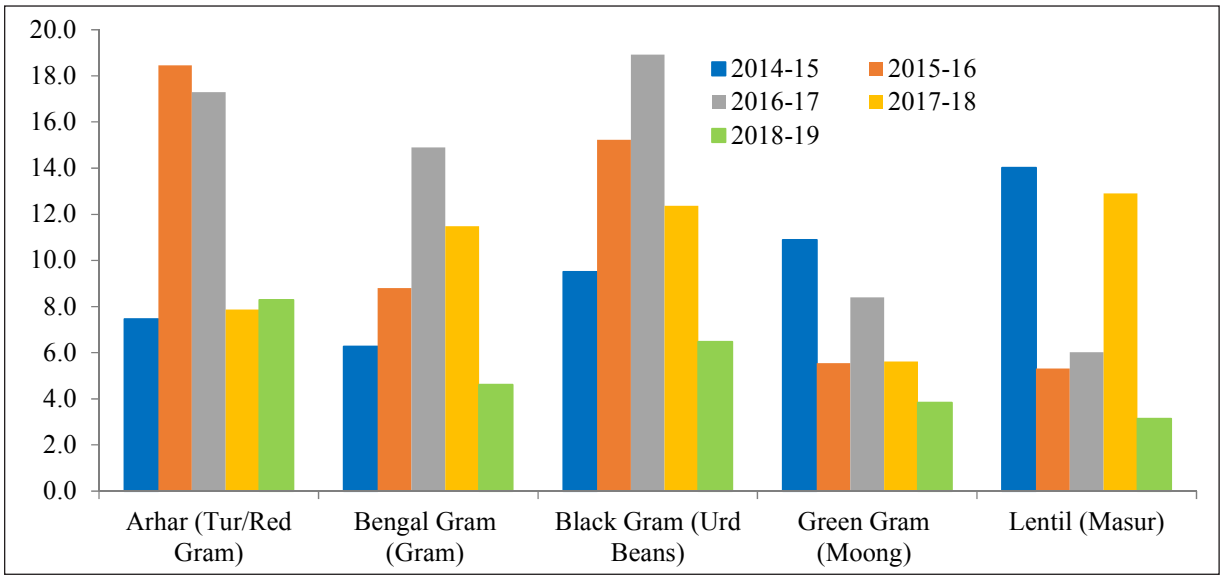

स्रोत: एगमार्गनेट आंकड़ों से गणना की गई है।

की संभावना होती है। इस प्रकार, 'कोर इन्फ्लेशन' में मुद्रास्फीति का आधारभूत रूप निहित होता है और इसीलिए यह काफी स्थायी होता है। मुद्रास्फीति के 'नॉन-कोर' घटकों के विपरीत 'कोर इन्फ्लेशन' पर अस्थायी घटकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है भारत में कोर इन्फ्लेशन को प्रमुख रूप से हेडलाईन इन्फ्लेशन में से अत्यधिक उतार-चढ़ाव वाले घटकों को निकाल कर मापा जाता है। अपनी विशेष प्रकृति के कारण खाद्य पदार्थ और ईंधन अत्यधिक उतार-चढ़ाव वाले घटक होते हैं। इस प्रकार, हैडलाइन मुद्रास्फीति में से खाद्य और ईंधन घटकों को निकालकर कोर मुद्रास्फीति तक पहुंचा जाता है। हैडलाइन मुद्रास्फीति में अल्पावधि परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव आते हैं इसलिए कई देशों के केन्द्रीय बैंक कोर मुद्रास्फीति पर ही ध्यान रखते हैं।

4.7 सीपीआई-सी आधारित 'कोर इन्फ्लेशन' जो कि खाद्य पदार्थों और ईंधन समूहों को निकालने के बाद सीपीआई के समान होता है, अपनी सीपीआई-सी की नयी श्रृंखला के प्रारम्भ से ही 4 प्रतिशत से ऊपर टिका है। सीपीआई-सी आधारित कोर इन्फ्लेशन 2017-18 में 4.6 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 5.8 प्रतिशत हो गया है। हालांकि, यह नवम्बर 2018 के 5.7 प्रतिशत से कम होकर अप्रैल 2019 में 4.5 प्रतिशत भी हो गया था (चित्र-3)। रिफाइन्ड कोर इन्फ्लेशन, जो कि खाद्य पदार्थों, ईंधन समूह, पेट्रोल और डीजल को पृथक करने के बाद सी पी आई के बराबर होता है, वह भी कोर इन्फ्लेशन के नजदीक आ गया है और यह 2017-18 में 4.6 प्रतिशत की तुलना में 2018-19 में 5.7 प्रतिशत हो गया था और अप्रैल 2019 में 4.8 प्रतिशत पर आ गया।

चित्र-3: कोर आधारित सी पी आई-सी प्रतिशत में

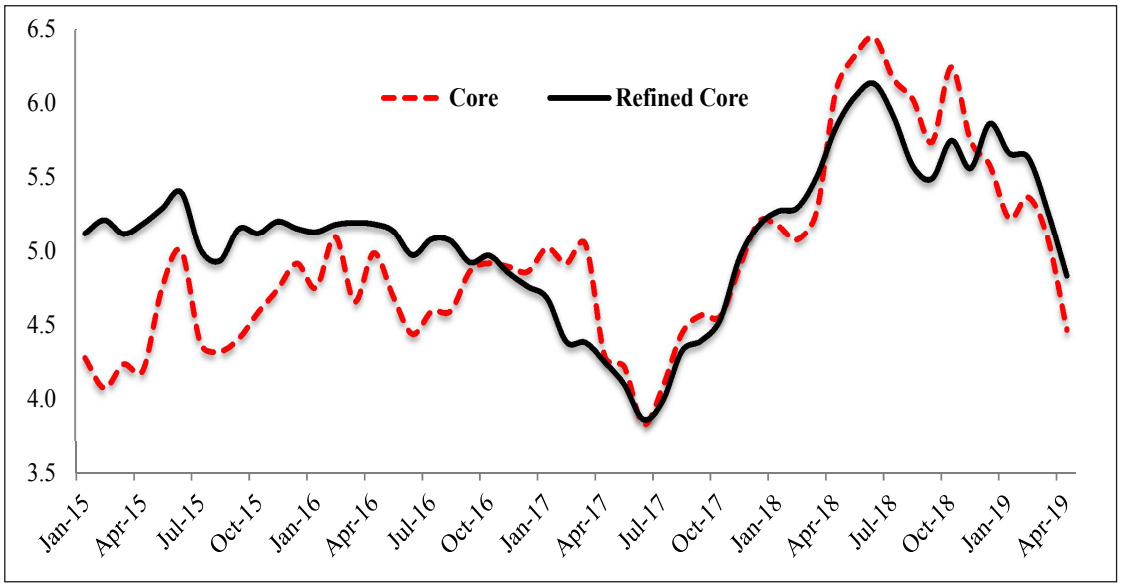

स्रोत: सीएसओ आंकड़ों से परिकलित किया गया है।

मुद्रास्फीति के कारक

4.8 अखिल भारतीय स्तर पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सीपीआई-सी मुद्रास्फीति के इन मुख्य समूहों से प्रभावित रही जैसे कि घर (आवासीय), ईंधन तथा बिजली समूह (चित्र-4) जैसे कि चित्र-5 में देखा जा सकता है, वस्तु मुद्रास्फीति जो कि सीपीआई-सी का 76.6 प्रतिशत अंश थी, वित्तीय वर्ष 2017-18 में 3.2 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 2.6 प्रतिशत हो गयी थी। इसके विपरीत सेवा की मुद्रास्फीति जो कि 23.4 प्रतिशत भाग थी, वित्तीय वर्ष 2017-18 में 5.0 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 6.3 प्रतिशत हो गयी थी।

4.9 वस्तु मुद्रास्फीति की तुलना में सेवा में मुद्रास्फीति

चित्र 4: 2017-18 और 2018-19 में उपभोक्ता कीमत सूचकांक संयुक्त मुद्रास्फीति में योगदान (हिस्सा प्रतिशत में)

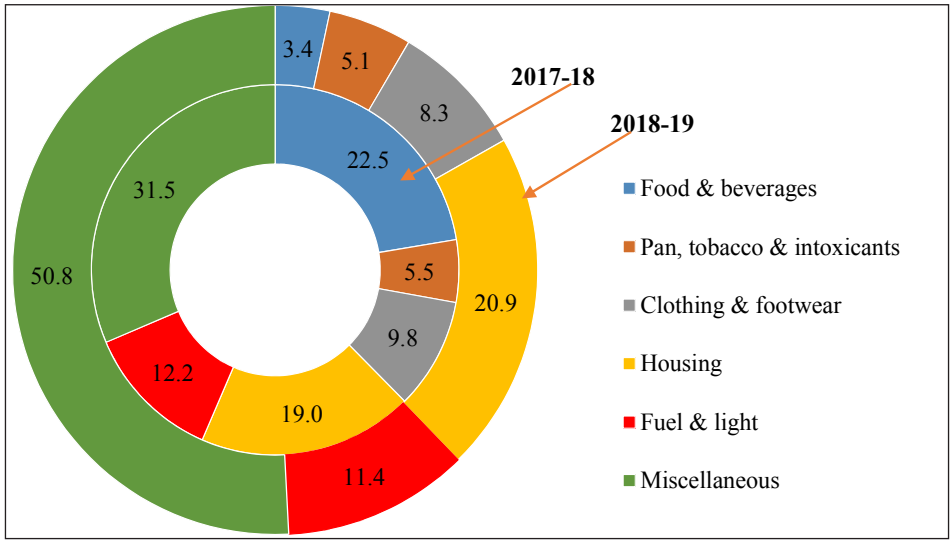

स्रोत: सीएसओ आंकड़ों से परिकलित किया गया है।

अधिक रही है और दोनों के बीच अन्तर बढ़ रहा है (चित्र-5 और 6)। हाल ही में, सेवा मुद्रास्फीति ने हेडलाईन मुद्रास्फीति को प्रभावित किया है, इसने अपने भार से अधिक का (सीपीआई-सी में 23.4 प्रतिशत) का योगदान दिया है।(चित्र-6) सेवाओं की 40 मदें सीपीआई-सी में 23.37 प्रतिशत हिस्सा रखती है। सेवाक्षेत्र में आवासीय मद उच्चतम रहा, जो (10. 07 प्रतिशत), उसके बाद परिवहन और संचार (4. 59 प्रतिशत), शिक्षा (3.51 प्रतिशत) और स्वास्थ्य (1.82 प्रतिशत) आते हैं (सारणी-4)। ड्राइविंग सेवा मुद्रास्फीति के निर्धारण में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और संचार नें मुख्य योगदान दिया है (चित्र-9 से 11 देखें)। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य मुद्रास्फीति अधिक प्रमुख थी, जो संभवत: आपूर्ति बाधा के कारण रही हो। बॉक्स-I शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा क्षेत्र के परिवहन घटक की गतिशील मुद्रास्फीति की गत्यात्मकता को प्रस्तुत करता है।

चित्र 5: माल एवं सेवाओ मे सी पी आई मुद्रास्फीति प्रतिशत में

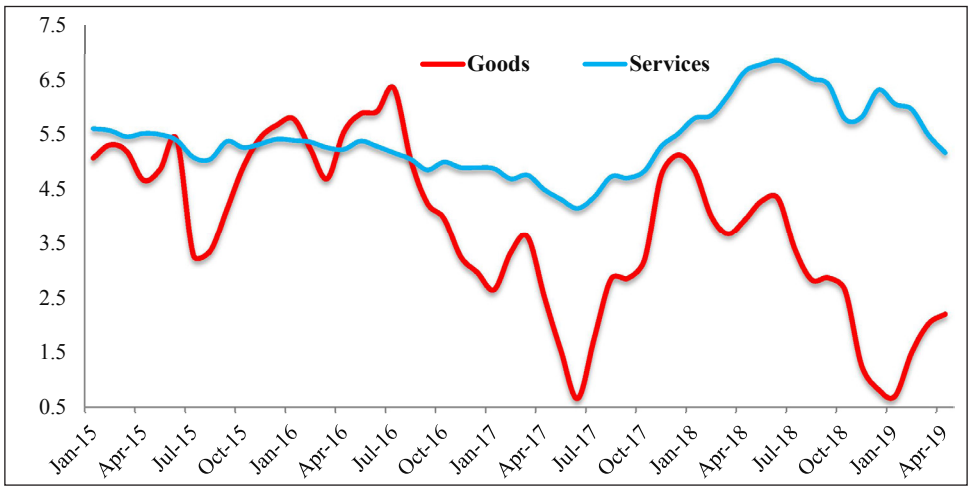

स्रोत: सीएसओ आंकड़ों से परिकलित किया गया है।

चित्र 6: हेडलाइन सी पी आई मुद्रास्फीति में माल एवं सेवाओं को योगदान

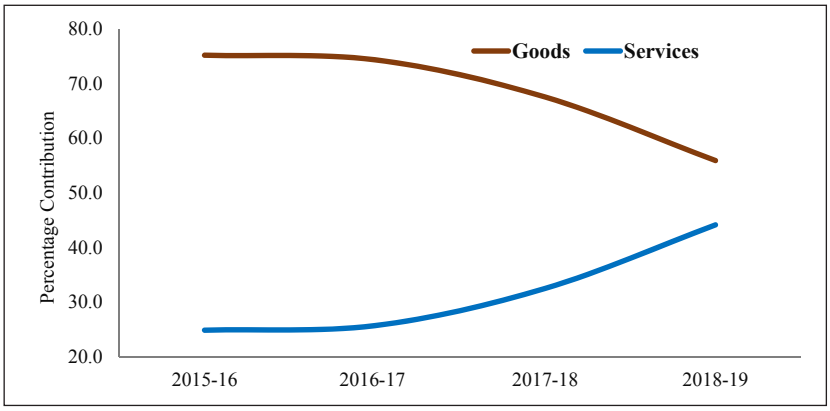

स्रोत: सीएसओ आंकड़ों से परिकलित किया गया है।

तालिका 4: सीपीआई-सी का माल और सेवा के 'भारों' और मदों में विभाजन

	कुल		माल		सेवाएं	
विवरण	वजन	मदें	वजन	मदें	वजन	मदें
आवास	10.07	4			10.07	4
परिवहन एवं संचार	8.59	21	4.00	8	4.59	13
शिक्षा	4.46	5	0.95	2	3.51	3
स्वास्थ्य	5.89	7	4.07	3	1.82	4
मनोरंजन एवं मन-बहलाव	1.68	17	0.59	9	1.10	8
पारिवारिक माल एवं सेवाएं	3.80	48	2.93	44	0.88	4
निजी देखभाल एवं और प्रभाव	3.89	16	3.34	15	0.55	1
परिधान	5.58	22	5.06	20	0.51	2
अनाज और उत्पादन	9.67	20	9.35	19	0.32	1
अन्य	46.37	139	46.34	139	-	-
सभी समूह	100	299	76.63	259	23.37	40

स्रोत: सीएसओ आंकड़ों से परिकलित किया गया है।

चित्र 7: सीपीआई-ग्रामीण मुद्रास्फीति में स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन एवं संचार का अंशदान

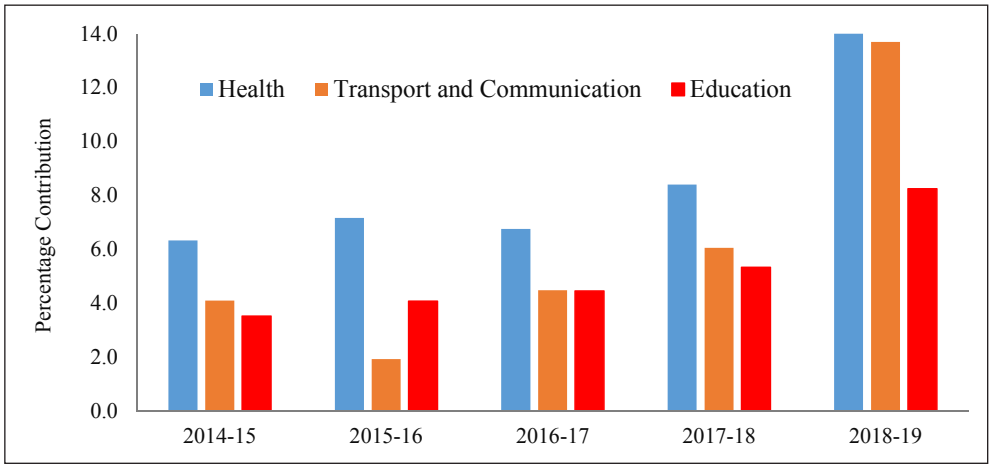

स्रोत: सीएसओ आंकड़ों से परिकलित किया गया है।

चित्र 8: सीपीआई-शहरी मुद्रास्फीति में स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन एवं संचार-शहरी अंशदान

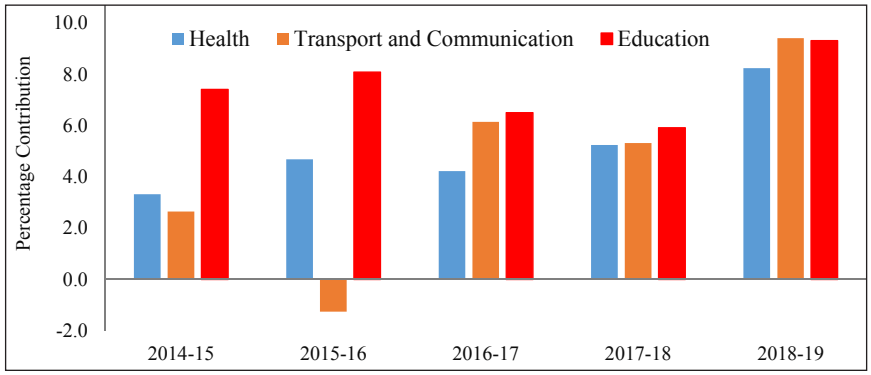

स्रोत: सीएसओ आंकड़ों से परिकलित किया गया है।

चित्र 9: सीपीआई-संयुक्त मुद्रास्फीति में स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन एवं संचार का प्रतिशत में योगदान

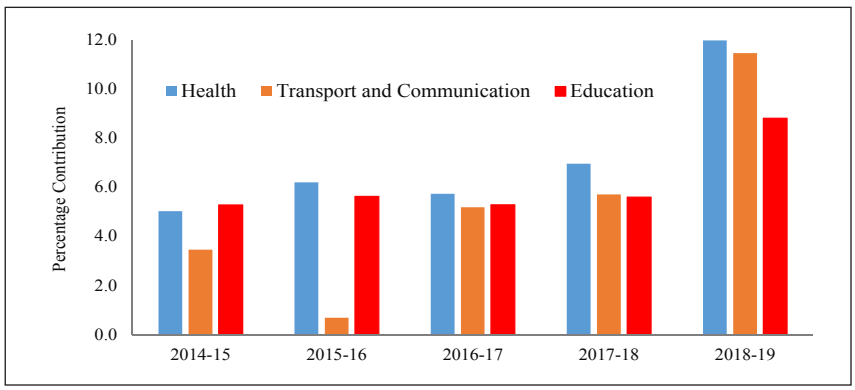

स्रोत: सीएसओ आंकड़ों से परिकलित किया गया है।

ग्रामीण–शहरी मुद्रास्फीति

4.10 शहरी और ग्रामीण मुद्रास्फीति दोनों में कमी को भी वर्तमान में मुद्रास्फीति के निम्न होने का कारण माना गया है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2018-19 में निम्न शहरी मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति की तुलना जब ग्रामीण मुद्रास्फीति से की गई तो पाया गया कि वह संतुलित हो रही है। जुलाई 2018 से ग्रामीण मुद्रास्फीति में शहरी मुद्रास्फीति से अधिक तेजी से गिरावट आई है परिणामस्वरूप हैडलाइन मुद्रास्फीति में गिरावट आई है। खाद्य मुद्रास्फीति में संयम के कारण ग्रामीण मुद्रास्फीति में कमी आई है जो कि छह महीनों में (अक्टूबर 2018 से मार्च 2019) ऋणात्मक रही है। पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण मुद्रास्फीति को निर्धारित करने में खाद्य की महत्ता घटती जा रही है। इसके विपरीत, ग्रामीण मुद्रास्फीति को निर्धारित करने वाली सेवाओं में विविध वर्ग की भूमिका बढ़ गई है। (चित्र 10).

4.11 वर्ष 2018-19 में सीपीआई (ग्रामीण) का मुख्य प्रचालक विविध वर्ग रहा है- यह इस स्फीति 70 प्रतिशत अंश के लिए उत्तरदायी था। शहरी क्षेत्रों के भी विविध वर्ग का स्फीति में योगदान वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान लगभग इतना ही रहा है। (चित्र 11)।

बॉक्स 1: सेवा मुद्रास्फीति के घटकों का विश्लेषण

I. शिक्षा

शिक्षा जिसका संयुक्त सीपीआई में 4.46 प्रतिशत का भार है, 5 मदों में बंटी है। इन पांच मदों में, जैसे कि किताबें जर्नल्स, फर्स्ट हैंड, और लेखन सामाग्री, फोटो कापी शुल्क ऐसे सामान हैं, जिनका भार 0.95 प्रतिशत बैठता है। बाकी तीन मद जैसे कि, ट्यूशन और अन्य फीस (स्कूल, कालेज, आदि), प्राइवेट ट्यूटर/कोचिंग सेंटर और अन्य शिक्षा पर खर्च (जिसमें वेब आधारित प्रशिक्षण हेतु नामांकन शुल्क भी शामिल है) सेवा क्षेत्र में आते हैं और इनका भार 3.51 प्रतिशत होता है। जनवरी 2015 से किए जा रहे मासिक संयुक्त सी पी आई डाटा के विश्लेषण से पता चलता है कि, सेवाओं की अपेक्षा सामान की मुद्रास्फीति कम रही है (चित्र 1)। प्राइवेट ट्यूटर्स कोचिंग सेंटर्स और ट्यूशन तथा अन्य शुल्क (स्कूल, कालेज, आदि) में 2018-19 के दौरान मुद्रास्फीति बढ़ी है।

एक लंबी समयावधि में शिक्षा उप-समूह के मुद्रास्फीति का विश्लेषण करते समय हमने औद्योगिक कार्मिकों के सीपीआई का प्रयोग किया है। नीचे दिये गए चित्र-2 में शिक्षा उप-समूह के सेवा घटक को सीपीआई-आई डब्ल्यू में दर्शाया गया है। प्राइमरी स्कूलों में मुद्रास्फीति में 2010-11 से कमी आ रही है। और 2012-13 में यह (-)21.5 प्रतिशत के निम्नतम स्तर पर आ गयी थी। सेकंडरी स्कूलों की फीस में भी 2009-10 से 2012-13 में मुद्रास्फीति कम हुई है। स्कूल फीस के विपरीत, जो कि 2009-10 से 2014-15 तक कम हुई है या इसमें मामूली बढ़ोत्तरी हुई है, कालेज और ट्यूशन फीस में इस अवधि के दौरान बढ़ोत्तरी देखी गयी है। हाल के वर्षों में शिक्षा संबंधी इन घटकों में सामान्य सी मुद्रास्फीति देखी गयी है। प्राइमरी स्कूल की फीस में मुद्रास्फीति में जो कमी आई है वह संभवत: 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने का परिणाम है।

चित्र 1: शिक्षा के माल और सेवा उप-समूह की सीपीआई-सी पर आधारित मुद्रास्फीति

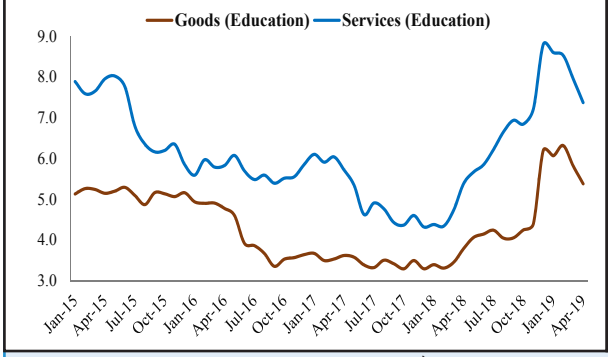

स्रोत: सीएसओ आंकड़ों से परिकलित किया गया है।

चित्र 2: शिक्षा मनोरंजन और मनोविनोद के अन्तर्गत मदों की सीपीआई-आईडब्ल्यू पर आधारित मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)

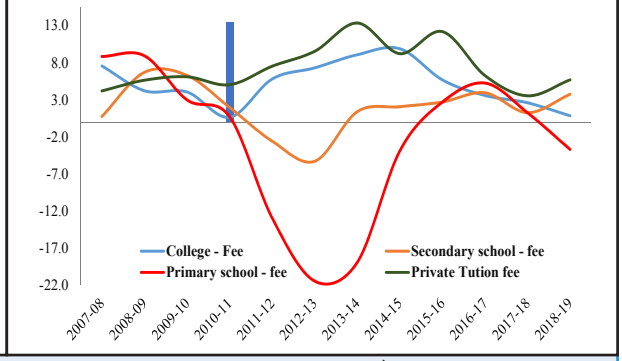

स्रोत: श्रम ब्यूरो के आंकड़ों से गणना की गई है।

II. स्वास्थ्य

स्वास्थ्य क्षेत्र संयुक्त सीपीआई में 5.89 प्रतिशत भार के साथ 7 मदों में फैला हुआ है। उन सात मदों में से इन तीन मदों अर्थात- 'चिकित्सा (गैर-संस्थागत), 'परिवार नियोजन उपकरण' और 'चश्मा' का भार 4.07 प्रतिशत हैं। शेष चार मदों में जैसे 'अस्पताल और नर्सिंग होम प्रभार', 'अन्य चिकित्सा खर्चे (गैर-संस्थागत)'; 'डाक्टर/शल्य चिकित्सक शुल्क-प्रथम परामर्श (गैर-संस्थागत) और एक्स-रे, ईसीजी, रोगविज्ञान संबंधी जांच, 1.82 प्रतिशत भार के साथ सेवा क्षेत्र से संबंध रखते हैं।

स्वास्थ्य के सेवा घटकों में उसमें निहित वस्तुओं की अपेक्षा अधिक तीव्र मुद्रास्फीति दिखाई दी है। तथापि, पिछले कुछ महीनों में उसमें वापिस होने का रुझान दिखाई दे रहा है (चित्र 3)।

चित्र 3 माल एवं सेवाओं द्वारा स्वास्थ्य उप-समूह हेतु सीपीआई-सी पर आधारित मुद्रास्फीति प्रतिशत में।

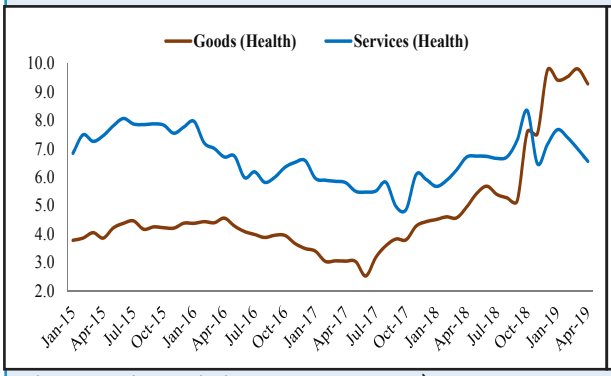

स्रोत: सीएसओ आंकड़ों से परिकलित किया गया है।

चित्र 4: मेडिकल केयर उप-समूह के अन्तर्गत मदों के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू आधारित मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)

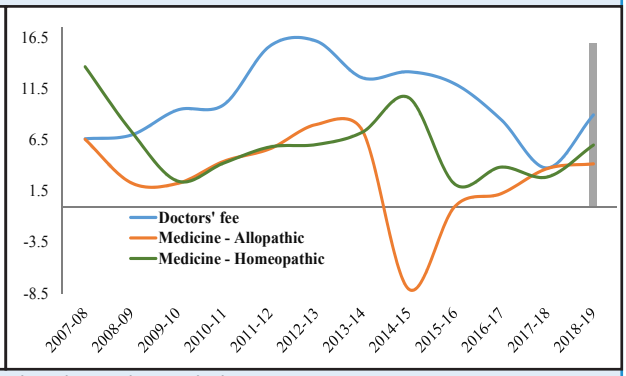

स्रोत: लेबर ब्यूरो आंकड़ों से परिकलित।

III. यातायात और संचार

संयुक्त सीपीआई में यातायात और संचार का भार 8.59 प्रतिशत और 21 मदों तक फैला हुआ है। इन सभी 21 मदों में 8 मदें जैसे कि मोटर कार, जीप, मोटर साइकिल, स्कूटर साइकिल (बिना सहायक सामग्री के), टायर और ट्यूब, 'वाहन के लिए पेट्रोल', 'वाहन के लिए डीजल', वाहन के लिए चिकनाई और अन्य ईंधन, मोबाइल हैण्डसैट वह सामान है जिनका भार 4 प्रतिशत है। शेष 13 मदें जो कि 'अन्य ढुलाई खर्च', रेलवे किराया, बस/ट्रेन किराया, टैक्सी, 'ऑटो-रिक्शा किराया', रिक्शा (हाथ से चलाने वाले और साइकिल), घोड़ा गाड़ी किराया, स्कूल बस, वैन इत्यादि हवाई किराया (सामान्य): किफायती वर्ग (वयस्क), 'स्टीमर, नाव किराया', 'पोर्टर दरें', दूरभाष दरें, लैंडलाइन, दूरभाष दरें: मोबाइल और इंटरनेट खर्चे इन सेवाओं का 4.59 प्रतिशत भार लिए हुए है।

औसतन यातायात और संचार के अंतर्गत सेवाओं के घटकों में वस्तुओं की तुलना में अधिक मुद्रास्फीति देखी गई है। हालांकि, सेवाओं की तुलना में वस्तुओं में अस्थिरता अधिक है। (चित्र 5)। सीपीआई-डब्लू के आंकड़ों का विश्लेषण यह इंगित करता है कि कुछ वर्षों से ''दूरभाष'' दरों में मुद्रास्फीति में स्थिरता जारी है। (चित्र 6)। वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2014-15 के बीच मुख्य रूप से तेल की उच्च कीमतों के कारण ''बस किराया'' और ऑटो रिक्शा किराया 6 प्रतिशत से ऊपर रहा है। वर्ष 2014-15 के पश्चात् 'बस किराया' और 'ऑटो रिक्शा किराया' में गिरावट के लिए कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और अक्टूबर 2014 में डीजल की कीमतों में अविनियमन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वर्ष 2013-14 में 'रेल किराया' की मुद्रास्फीति में एकाएक वृद्धि का कारण रेल किराए में तीव्र वृद्धि है।

चित्र 5: माल एवं सेवा द्वारा 'परिवहन एवं संचार' उप-समूह के लिए सीपीआई-सी आधारित मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)

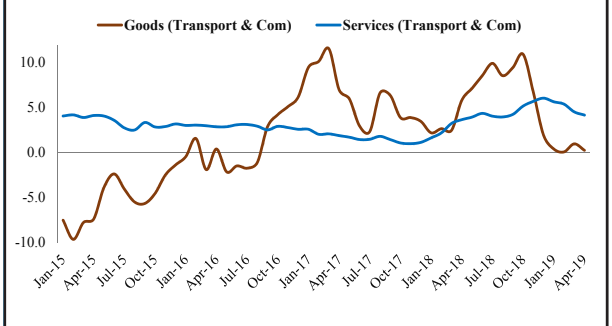

स्रोत: सीएसओ आंकड़ों से परिकलित किया गया है।

चित्र 6: परिवहन एवं संचार उप-समूहों के अन्तर्गत मदों के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू

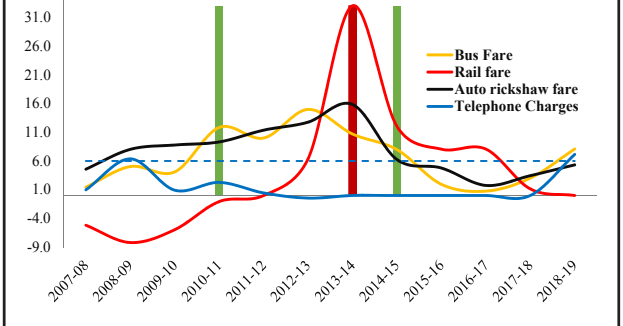

स्रोत: लेबर ब्यूरो आंकड़ों से परिकलित।

चित्र 10: सीपीआई-ग्रामीण मुद्रास्फीति में विभिन्न समूहों का अंशदान

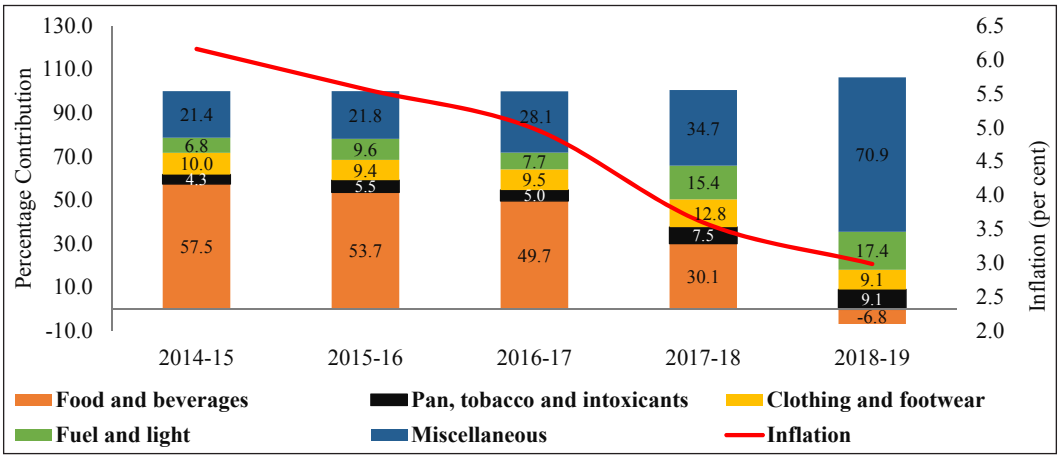

स्रोत: सीएसओ आंकड़ों से परिकलित किया गया है।

चित्र 11: सीपीआई-शहरी मुद्रास्फीति में विभिन्न समूहों का अंशदान

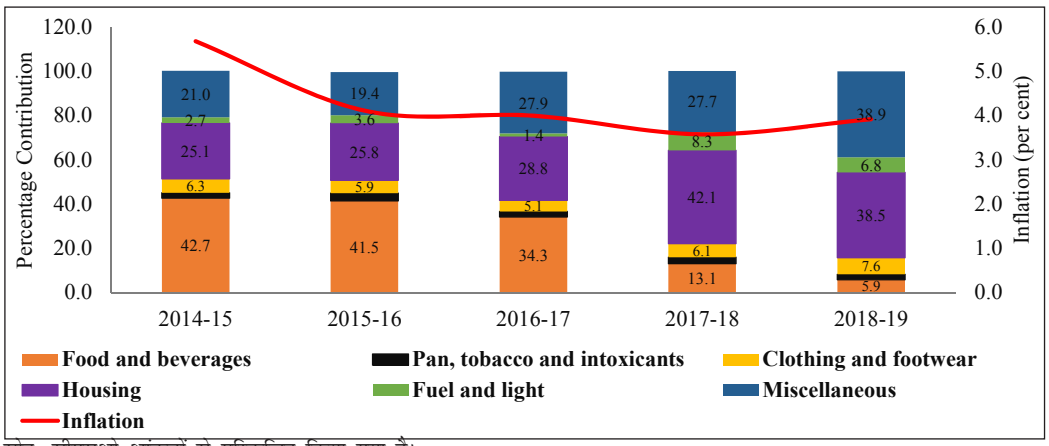

स्रोत: सीएसओ आंकड़ों से परिकलित किया गया है।

बॉक्स 2: आवास कीमत सूचकांक

I. एनएचबी रेजीडेक्स

आवास कीमत सूचकांक (एचपीआई) वह व्यवस्था है जिससे किसी भौगोलिक सीमा के भीतर आवासीय परिसंपत्तियों की कीमतों हो रही कमी व वृद्धि का मापन किया जाता है। देश में सरकार की ओर से पहला आवासीय मूल सूचकांक 'एनएचबी रेजीडेक्स' जुलाई 2007 में नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा शुरू किया गया। इतने समय बाद 2017-18 को आधार वर्ष माना गया है, जिसके आधार पर नवीनतम जानकारी एकत्र की जाती है और इससे देश में वर्तमान आर्थिक स्थिति का पता चलता है।

इस समय, वित्तीय वर्ष 2017-18 को आधार वर्ष मानते हुये नेशनल हाउसिंग बैंक 50 शहरों में त्रैमासिक आधार पर 'एनएचबी रेजीडेक्स' का प्रकाशन कर रहा है। ये 50 शहर 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं और इनमें से 33 उन स्मार्ट शहरों में आते हैं जिनकी सूची भारत सरकार ने जारी की है। इन सूचकांकों की गणना लेसपियर्स विधि का प्रयोग करके और चार त्रैमासिक भारित तथा परिवर्तनशील औसत के आधार पर की जाती है।

आकलन मूल्य पर एच पी आई की गणना ऋणदाता मूल्यांकन डाटा का प्रयोग करके की जाती है जो बैंकों/हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनियों से प्राप्त होते हैं और जबकि निर्माणाधीन परिसंपत्तयों के लिए बाजार कीमत पर एच पी आई गणना निर्माणाधीन

परिसंपत्तियों के बाजार कीमत आंकड़ों पर आधारित होती है जिसे डेवेलपर्स, बिल्डर्स और दलालों से प्राप्त किया जाता है। एन एच बी 50 शहरों के सूचकांकों के आधार पर आकलन और बाजार कीमत के अनुसार संयुक्त एच पी आई भी प्रकाशित करता है। इस संयुक्त सूचकांक को शहर स्तरीय सूचकांक में जनसंख्या भार का प्रयोग करके निकाला जाता है।

आकलन कीमतों पर संयुक्त एच पी आई से संबन्धित आवास कीमतों की वृद्धि दर को चित्र 1 में दर्शाया गया है। चित्र 2 में उन आवासीय कीमतों को दर्शाया गया है जो कि निर्माणाधीन परिसम्पत्तियों से संबन्धित है और ये बाजार कीमतों पर आधारित है।

चित्र 1: निर्धारण कीमतों पर मिश्रित एचपीआई आधारित वृद्धि (प्रतिशत में)

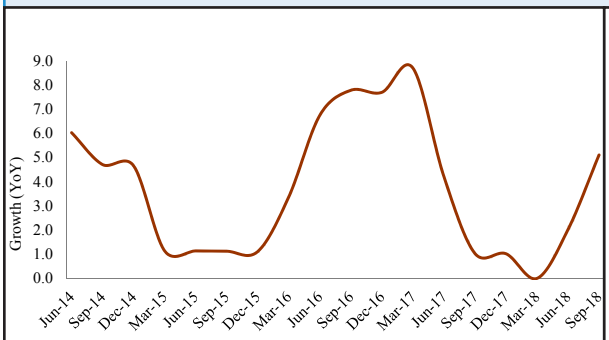

चित्र 2: निर्माणधीन संपत्तियों के लिए बाजार कीमतों पर वृद्धि दर पर आधारित समग्र एचपीआई वृद्धि दर (प्रतिशत में)

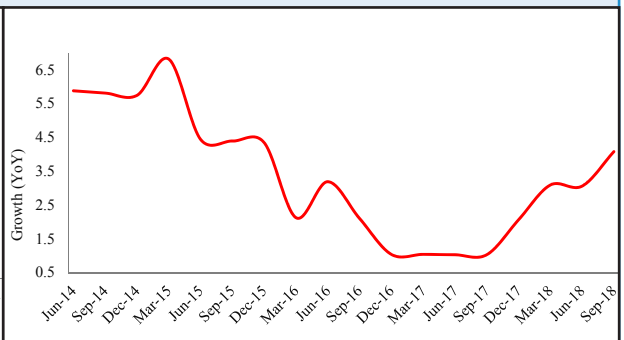

II. एचपीआई (आरबीआई)

वर्ष 2007 में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुम्बई [आधार 2002-03=100] शहर के लिए तिमाही आवास कीमत सूचकांक एचपीआई का संकलन करना शुरु कर दिया। तबसे, इसने अपने क्षेत्र को नौ अन्य शहरों में विस्तारित किया, अपने आधार को 2010-11=100 तक संशोधित किया है और एक संयुक्त अखिल भारतीय एचपीआई का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया है। आरबीआई का तिमाही एचपीआई दस प्रमुख शहरों के आवासीय पंजीकरण प्राधिकरण से प्राप्त लेन-देन के आंकड़ों पर आधारित होती है। आवासीय कीमतों में वर्षानुगत वृद्धि/गिरावट को दर्शाता है (चित्र 3 को देखें)।

चित्र 3: आरबीआई का अखिल भारतीय एचपीआई वृद्धि दर (प्रतिशत में)

राज्यों में मुद्रास्फीति

4.12 2018-19 के दौरान कई राज्यों ने सीपीआई मुद्रास्फीति में गिरावट देखी है (चित्र 14)। वित्तिय वर्ष 2018-19 में 23 राज्यों/संघ शासित प्रदेशो में मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत से कम थी। (चित्र 12)। वित्तीय वर्ष 2017-2018 में मुद्रास्फीति 1.5 प्रतिशत से 12.4 प्रतिशत की तुलना में राज्यों में वित्तिय वर्ष 2018-2019 में (-)1.9 प्रतिशत से 8.9 प्रतिशत के बीच मे थी।(चित्र 13)। सोलह राज्यों/संघ शासित

प्रदेशो में मुद्रास्फीति दर वित्तीय वर्ष 2018-2019 के औसत अखिल भारतीय से कम है जिसमें दमन और दीव में सबसे कम और उसके बाद हिमाचल प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश हैं।

4.13 ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2017-2018 में तेरह राज्यों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-2019 में सोलह मुख्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशो में मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत से कम दर्ज किया। (चित्र 14)।

चित्र 12: सीपीआई मुद्रास्फीति 2018-19 (प्रतिशत में)

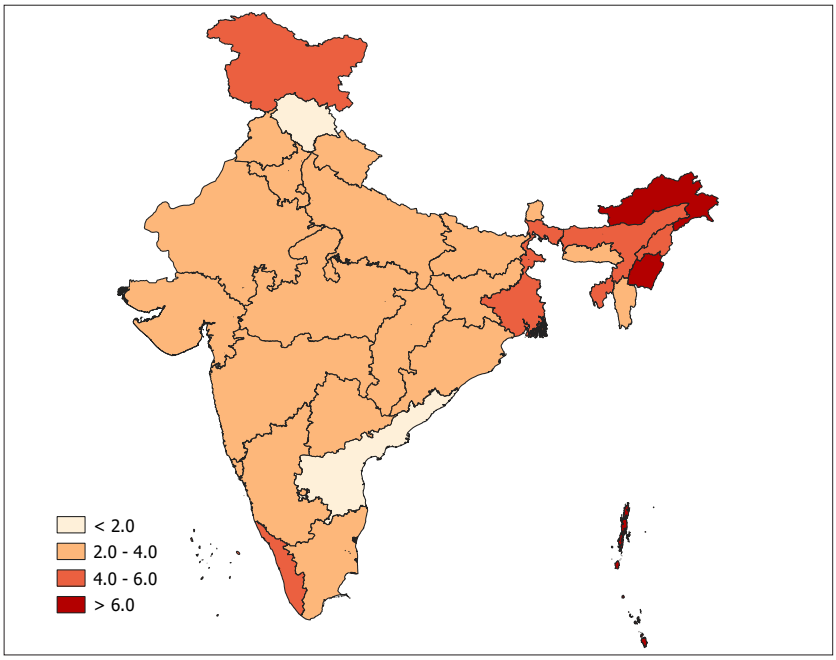

स्रोत: सीएसओ से प्राप्त आंकड़े।

चित्र 13: सीपीआई, मुद्रास्फीति 2017-18 (प्रतिशत में)

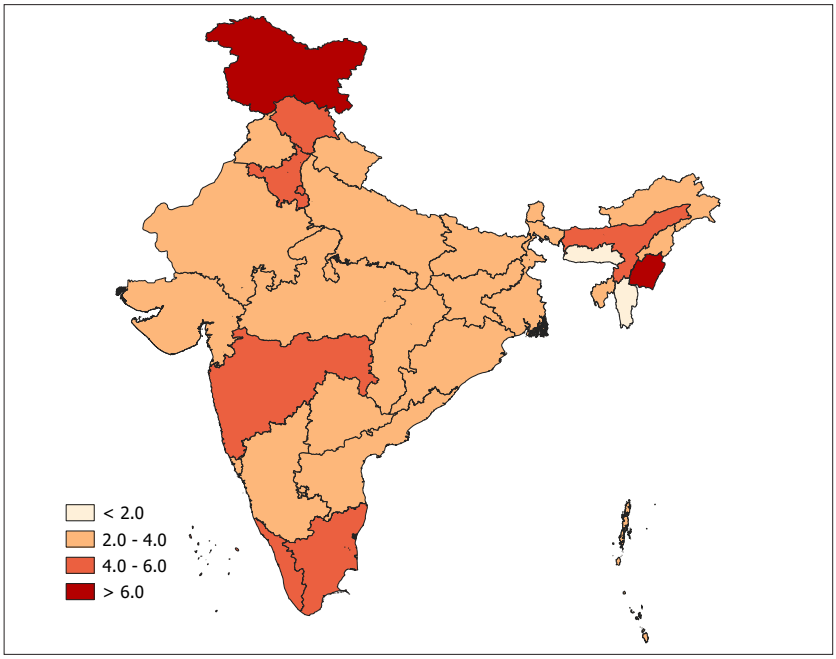

स्रोत: सीएसओ से प्राप्त आंकड़े।

चित्र 14: प्रमुख राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मुद्रास्फीति सीपीआई (ग्रामीण) (प्रतिशत में)

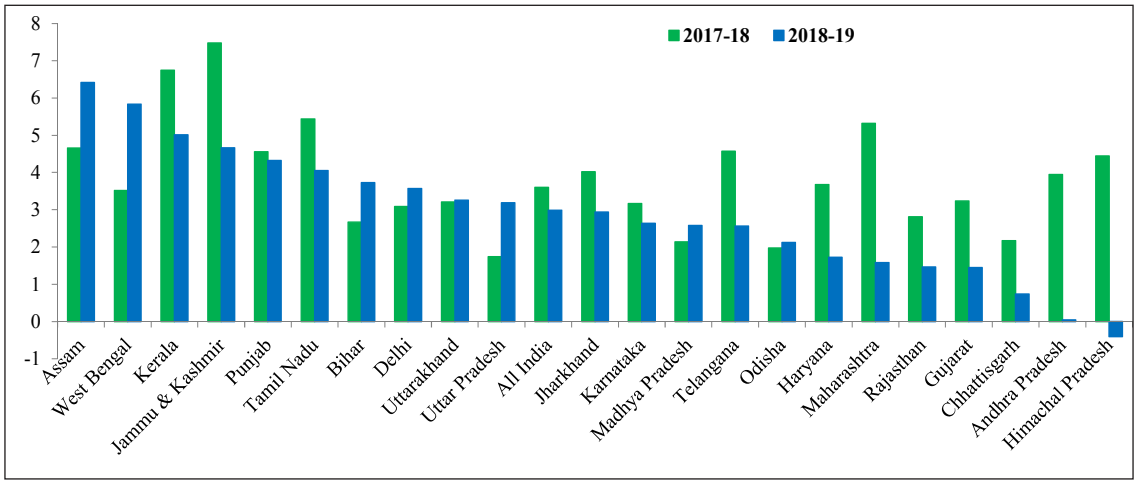

स्रोत: सीएसओ आंकड़ों से परिकलित किया गया है।

चित्र 15: प्रमुख राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मुद्रास्फीति सीपीआई (शहरी) (प्रतिशत में)

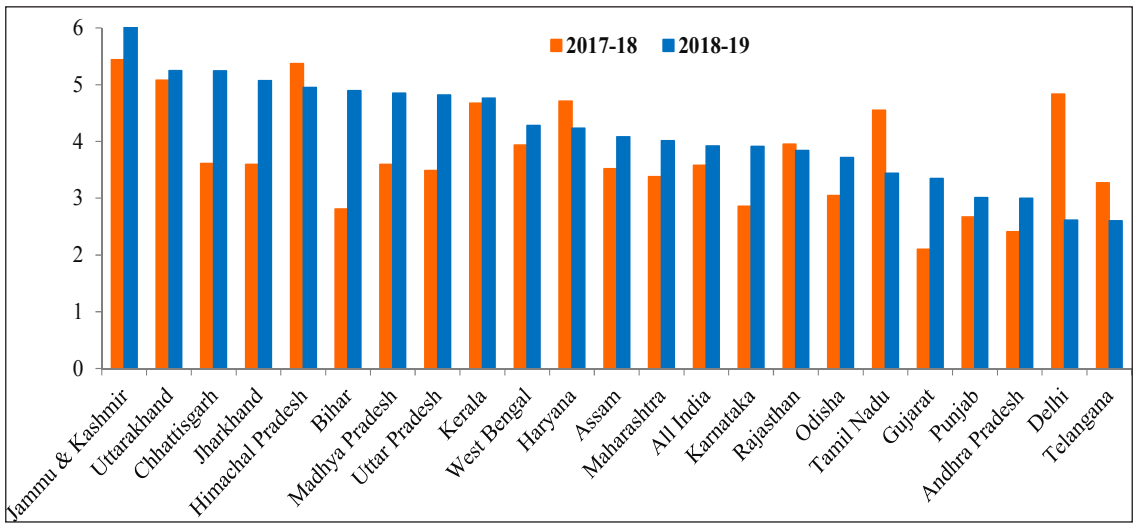

स्रोत: सीएसओ आंकड़ों से परिकलित किया गया है।

हालांकि, शहरी क्षेत्र के मामलों में 2017-2018 में पन्द्रह राज्यों के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2018-2019 में नौ राज्यों ने 4 प्रतिशत से कम मुद्रास्फीति दर्ज की है। (चित्र 15)

वस्तु कीमतों में वैश्विक रुझान

4.14 विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित वस्तु कीमतों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में ऊर्जा वस्तु कीमतों में बढ़ोतरी के रुझान जारी रहे हैं। 2017-2018 में 16.8 प्रतिशत की तुलना में 2018-2019 में 22.1 प्रतिशत औसत मुद्रास्फीति दर्ज की गई है (चित्र 16)। अखिल भारतीय थोक कीमत सूचक के ''ईंधन और विद्युत'' घटक के उतार चढ़ाव विश्व बैंक ऊर्जा कीमत सूचकांक का अनुसरण करते हैं। वित्तीय वर्ष 2017-2018 के 8.1 प्रतिशत की तुलना वित्तीय वर्ष 2018-2019से की गई तब उसमें औसतन 11.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2018-2019 के दौरान विश्व बैंक की खाद्य कीमतों और साथ ही साथ खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) की खाद्य कीमतों में भी अवस्फीति दर्ज कराई गई है। 2018-2019

चित्र 16: विश्व बैंक मूल्य सूचकांक एवं एफएओ खाद्य मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति (एफएफपीआई) (प्रतिशत में)

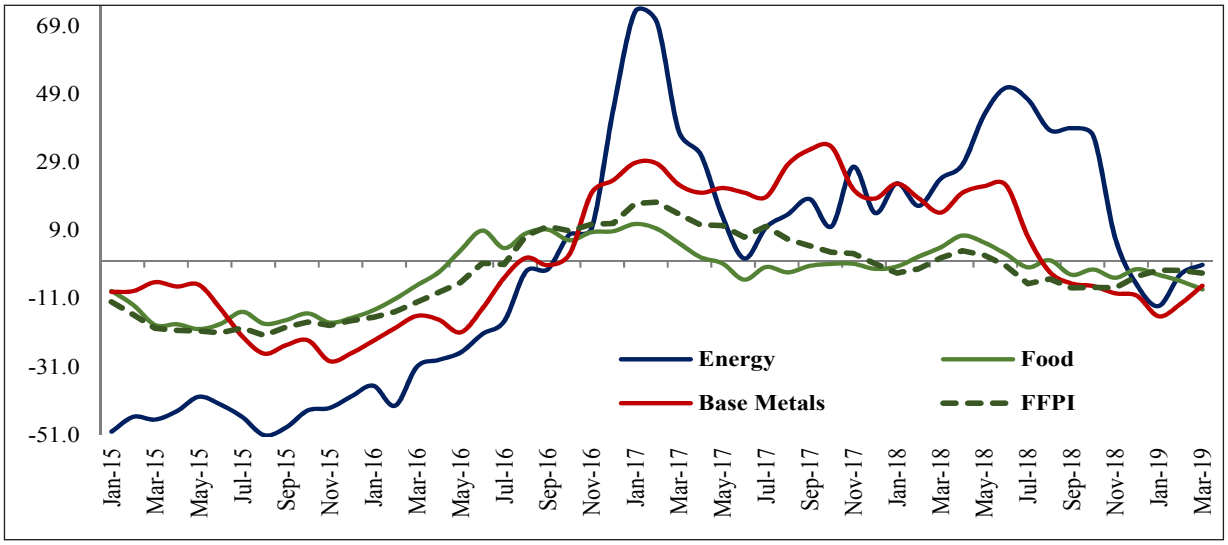

स्रोत: विश्व बैंक एवं एफएओ आंकड़ों से परिकलित किया गया है।

चित्र 17: डब्ल्यूपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)

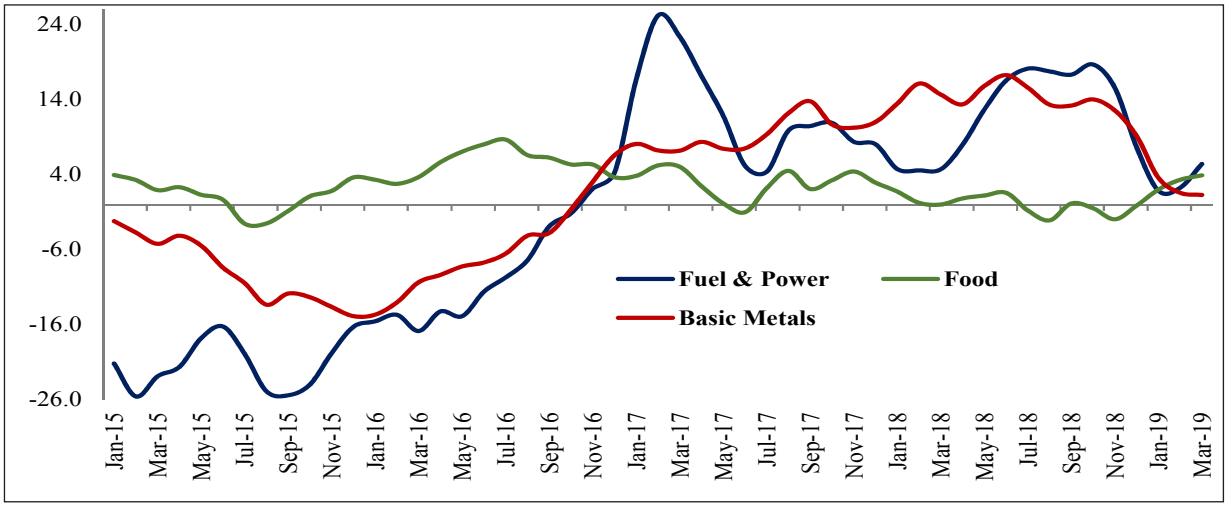

स्रोत: आर्थिक सलाहकार कार्यालय, डीपीआईआईटी आंकड़ों से परिकलित किया गया है।

के दौरान भारत में भी डब्लू पी आई आधारित खाद्य मुद्रास्फीति में भी गिरावट आई है (चित्र 17)।

मुद्रास्फीति को रोकने के प्रयास

4.15 केन्द्र सरकार लगातार कीमतों की स्थिति पर निगरानी रखती है क्योंकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना इसके नीतिगत सरोकारों का प्रमुख हिस्सा है। सरकार ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कई प्रकार के कदम उठाए हैं विशेषत: खाद्य मुद्रास्फीति को। इन कदमों में सामान्य कदम और विशिष्ट कदम दोनों ही शामिल है।

4.16. मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सामान्य रूप से निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं। पहला, जहां और जब भी जरुरत पड़ती है, राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है कि वे जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, विशेषकर तब जब जिन्सों की आपूर्ति कम हो रही हो। ऐसे उपाय विशेष रूप से आवश्यक जिन्स अधिनियम, 1955 और काला

बाजारी निवारक और आवश्यक जिन्स आपूर्ति बहाली अधिनियम, 1980 के अंतर्गत की जाती है। दूसरा, प्रमुख जिन्सों की कीमतों और इनकी उपलब्धता के बारे में उच्च स्तर पर समीक्षा बैठकें होती रहती हैं। इन बैठकों में मंत्रिस्तरीय समिति, सचिवों की समिति, अंतर्मन्त्रालयीन समिति, कीमत स्थिरीकरण कोष प्रबंधन समिति और अन्य विभाग स्तरीय समीक्षा समितियां आती हैं। तीसरा, दलहन और अन्य उन फसलवालों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमतों की घोषणा की जाती है जिनके उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाता है। इनसे खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ती है और कीमतों को कम रखने में मदद मिलती है, जिसका उद्देश्य दलहन, प्याज जैसी कृषि जिन्सों की कीमतों पर नियंत्रण रखना है। और अन्ततः सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष बनाया है ताकि उपलब्धता में सुधार और कीमतों में संतुलन हेतु खरीदे गए आलू, प्याज तथा दालों समेत कृषि वस्तुओं को मंदी के दौरान जारी किया जा सके।

4.17 सरकार ने जो विशेष उपाय किए हैं वे निम्नलिखित हैं: पहला, 2017-2018 और 2018-2019 की कमी वाली अवधि के दौरान, प्याज की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए पीएसएफ के अंतर्गत खरीदे गए स्टॉक से किफायती कीमतों पर प्याज को बेचा गया। दूसरा, बफर की दालों में कीमत प्रबंधन, संस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने जैसे दोपहर की भोजन योजना के लिए राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश को आपूर्ति, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना और जन वितरण योजना और खुले बाजार में बिक्री आदि को युक्तिपूर्ण बाजार हस्तक्षेप में उपयोग हो रहा है। इसके अतिरिक्त, बफर की दालों का उपयोग सेना और केन्द्रीय अर्धसैनिक बल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। तीसरा, सरसों के तेल को छोड़कर सभी प्रकार के तेलों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है। 5 किलो के ब्रांडेड उपभोक्ता पैकेटों में सरसों के तेल का निर्यात न्यूनतम समर्थन कीमत के अंतर्गत 900 अमेरिकी डालर प्रति मिलियन टन के हिसाब से निर्यात किए जाने की अनुमति दी गयी है और अंत में राज्यों/संघ राज्यों को यह शक्ति प्रदान की गयी है कि वे खाद्य तेलों के भंडारण पर अपनी सीमा तय कर सकते हैं और 13 जून, 2018 की एक अधिसूचना के माध्यम से खाद्य तेलों पर से नियंत्रण हटा लिया गया है।

निष्कर्ष

4.18 वित्त वर्ष 2018-19 में खाद्य पदार्थों में मुद्रास्फीति कम रही है। इस वर्ष दालों, सब्जियों और चीनी की कीमतों में कमी का रुख देखा गया है हालांकि कोर इन्फलेशन पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक रहा है।

अध्याय एक नजर में

- सीपीआई-सी पर आधारित हैडलाइन मुद्रास्फीति में वित्त वर्ष में लगातार पांचवीं बार गिरावट का रूझान रहा। यह विगत दो वर्षों में 4.0 प्रतिशत से नीचे बना रहा।
- गत पाँच वर्षों में उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफआई) पर आधारित खाद्य मुद्रा स्फीति भी गिरावट की स्थिति में रहा और गत दो वर्षों के लिए 2.0 प्रतिशत से नीचे बना रहा।
- वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान सीपीआई-सी आधारित मुख्य मुद्रास्फीति (खाद्य और तेल समुह के अतिरिक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में बढ़ा। तथापि इसमें मार्च 2019 से गिरावट आई।
- वित्त 2018-19 के दौरान सीपीआई-सी हैडलाइन मुद्रस्फीति के मुख्य अशंदाता है विविध, आवासन और तेल और प्रकाश समूह। हैडलाइन मुद्रास्फीति को आकार देने में सेवाओं की तुलनात्मक रूप से महत्व बढ़ा है।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण मुद्रास्फीति में वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2018-19 में गिरावट आई है। तथापि वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शहरी मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि हुई। बहुत से राज्यों में वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में कमी देखी गई है।